

## मध्य प्रदेश में "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम के तहत प्रमुख विकास

**Janardan Kukreja**

Research Scholar

Jiwaji University Gwalior , (M.P.)

**Prof. Ajay Kumar Mandil**

Professor

Government M.L.B. Arts And Commerce College, Gwalior (M.P.)

**Prof. Sanjeev Gupta**

Professor

Government Vranda Sahay Post Graduate College  
Dabra, Dist. Gwalior (M.P.)

**DECLARATION:** I AS AN AUTHOR OF THIS PAPER /ARTICLE, HERE BY DECLARE THAT THE PAPER SUBMITTED BY ME FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL IS COMPLETELY MY OWN GENUINE PAPER. IF ANY ISSUE REGARDING COPYRIGHT/PATENT/OTHER REAL AUTHOR ARISES, THE PUBLISHER WILL NOT BE LEGALLY RESPONSIBLE. IF ANY OF SUCH MATTERS OCCUR PUBLISHER MAY REMOVE MY CONTENT FROM THE JOURNAL WEBSITE. FOR THE REASON OF CONTENT AMENDMENT /OR ANY TECHNICAL ISSUE WITH NO VISIBILITY ON WEBSITE /UPDATES, I HAVE RESUBMITTED THIS PAPER FOR THE PUBLICATION.FOR ANY PUBLICATION MATTERS OR ANY INFORMATION INTENTIONALLY HIDDEN BY ME OR OTHERWISE, I SHALL BE LEGALLY RESPONSIBLE. (COMPLETE DECLARATION OF THE AUTHOR AT THE LAST PAGE OF THIS PAPER/ARTICLE)

### अमूर्त

पिछले दशक में भारत के गहन आर्थिक परिवर्तन को कई ऐतिहासिक सुधारों और नवीन पहलों से बढ़ावा मिला है। एक लचीले भारत के निर्माण की दिशा में ऐसा ही एक प्रमुख विचार-विमर्श वाला कदम मेक इन इंडिया कदम रहा है। 2014 में लॉन्च किया गया, यह इस बदलाव में सबसे आगे रहा है - जिससे भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा यह पेपर मेक इन इंडिया कार्यक्रम के विकास और वृद्धि पर नज़र डालता है क्योंकि इसे पहली बार 2014 में मेक इन इंडिया 2.0 कार्यक्रम और प्रस्तावित 3.0 कार्यक्रम के तहत विकसित कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। शोध का उद्देश्य यह जांचना है कि उद्योग विकास, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, कॉर्पोरेट कर में कमी, डिजिटल प्रशासन और ढांचागत परिवर्तनों के आधुनिकीकरण सहित राष्ट्रीय स्तर के नीतिगत सुधारों ने समग्र भारतीय विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे प्रभावित किया है। पेपर इस बात की भी जांच करता है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक गलियारों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, समूहों में विनिर्माण केंद्रों, लॉजिस्टिक्स वृद्धि और निवेशकों के लिए राज्य-अनुकूल नीतियों के माध्यम से इन विकासों को कैसे व्यवहार में लाया गया है। जीएसडीपी वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय, क्षेत्र-आधारित औद्योगिक विकास और एफडीआई प्रवाह की प्रवृत्ति की जांच से इस बात की विस्तृत जानकारी मिलती है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की क्रमिक प्रगति ने मध्य प्रदेश की औद्योगिक नींव और दीर्घकालिक आर्थिक परिवर्तनों को बेहतर बनाने में कैसे मदद की है। जैसा कि भारत 2047 में अपने शताब्दी वर्ष की प्रतीक्षा कर रहा है, मेक इन इंडिया की सफलता एक विकसित राष्ट्र बनने के उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में रीढ़ की हड्डी होगी।

## 1. प्रस्तावना

25 सितंबर 2014 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई, "मेक इन इंडिया" पहल भारत के राष्ट्र-निर्माण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 10 साल पूरे कर रही है। "मेक इन इंडिया" पहल भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने में आधारशिला रही है। औद्योगिक क्षमताओं को बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर देने के साथ, इस पहल का लक्ष्य भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना है।

मेक इन इंडिया कार्यक्रम ने भारतीय औद्योगिक और निवेश नीति ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव का एहसास कराया, जिसके तहत देश को दुनिया में विनिर्माण केंद्र में बदलने का लक्ष्य रखा गया। मध्य प्रदेश उन क्षेत्रों में से एक था जो राज्य स्तर पर सक्रिय रूप से लगे हुए थे, क्योंकि यह रणनीतिक रूप से स्थित था, इसका औद्योगिक आधार बढ़ रहा था, और नीतिगत माहौल अनुकूल था। यह पहल बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, व्यापार करने में आसानी की सुविधा और क्षेत्र-विशिष्ट सुधारों के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने का एक प्रयास था। इस संबंध में, मध्य प्रदेश ने राज्य के विकास उद्देश्यों को राष्ट्रीय विनिर्माण उद्देश्यों के अनुरूप लाने के लिए कई नीतिगत हस्तक्षेप और औद्योगिक प्रोत्साहन लागू किए हैं।

मेक इन इंडिया योजना के तहत मध्य प्रदेश ने औद्योगिक बुनियादी ढांचे में बड़ी बढ़त दर्ज की है। राज्य द्वारा नए औद्योगिक पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र और कपड़ा, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण सहित उद्योग से संबंधित क्लस्टर बनाए गए। मुख्य निवेश लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के आधुनिकीकरण पर निर्देशित थे, जिसमें सड़क पहुंच में वृद्धि, बिजली आपूर्ति की बेहतर विश्वसनीयता और मल्टीमॉडल परिवहन बुनियादी ढांचे शामिल थे। इन विकासों ने स्थानीय और विदेशी दोनों निवेशकों को लुभाने और बड़े और छोटे पैमाने की विनिर्माण फर्मों को विकसित करने में मदद करने के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार किया।

घटनाओं का दूसरा महत्वपूर्ण मोड़ यह था कि डिजिटल अनुमोदन, समय-सीमित मंजूरी, एकल-खिड़की-सुविधा और श्रम कानून के सरलीकरण में बदलाव के बाद से राज्य की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में काफी सुधार हुआ। मध्य प्रदेश ने ऑनलाइन भूमि आवंटन, लाइसेंसिंग, पर्यावरण मंजूरी और औद्योगिक पंजीकरण प्रणाली शुरू की, जिससे प्रक्रियाओं में समय की देरी कम हुई और निवेशकों का विश्वास बढ़ा। इन सुधारों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, स्टार्टअप नीति और उद्योग नीति प्रोत्साहन जैसे नीतिगत प्रोत्साहनों का समर्थन प्राप्त था, जिससे राज्य की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने में संयुक्त बल सक्षम हुआ।

कुल मिलाकर, मेक इन इंडिया कार्यक्रम मध्य प्रदेश में संरचनात्मक परिवर्तन के लिए एक प्रेरणा था। हालाँकि बाहरी झटकों और वैश्विक बाजार की स्थिति के कारण कुछ आर्थिक परिणाम वर्षों के साथ अलग-अलग रहे, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव औद्योगिक शक्ति में वृद्धि, विनिर्माण गतिविधि के विकास, बुनियादी ढांचे की वृद्धि और निवेश में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। ये रुझान एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र

के रूप में राज्य की बढ़ती क्षमता और स्थायी नवाचार-आधारित आर्थिक विकास की दिशा में इसके धीमे विकास पर जोर देते हैं।

## 2. मेक इन इंडिया

मेक इन इंडिया भारत सरकार का एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य निवेश को सुगम बनाना, नवाचार को बढ़ावा देना, कौशल विकास को बढ़ावा देना, बौद्धिक संपदा की रक्षा करना और देश में सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण अवसंरचना का निर्माण करना है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर से निवेश आकर्षित करना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना है। इसका नेतृत्व उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से अपने प्रथम स्वतंत्रता दिवस भाषण में इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा था, "मैं पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूँ: आइए, भारत में निर्माण कीजिए। दुनिया के किसी भी देश में जाकर बेचिए, लेकिन निर्माण यहीं कीजिए। हमारे पास कौशल, प्रतिभा, अनुशासन और कुछ कर गुजरने की इच्छा है। इस पहल की औपचारिक शुरुआत 25 सितंबर 2014 को श्री मोदी द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में भारत के दिग्गज व्यापारिक प्रतिनिधियों की उपस्थिति में की गई थी।

एक मजबूत विनिर्माण क्षेत्र का विकास भारत सरकार की एक प्रमुख प्राथमिकता है। मेक इन इंडिया उन शुरुआती 'वोकल फ़ॉर लोकल' पहलों में से एक था जिसने भारत के विनिर्माण क्षेत्र को दुनिया के सामने उजागर किया। इस क्षेत्र में न केवल आर्थिक विकास को नई ऊँचाइयों पर ले जाने की क्षमता है, बल्कि हमारे युवा श्रम बल के एक बड़े समूह को रोज़गार प्रदान करने की भी क्षमता है। मेक इन इंडिया पहल की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ रही हैं और वर्तमान में यह मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत निम्नलिखित 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है।

पिछले एक दशक में, "मेक इन इंडिया" पहल ने घरेलू विनिर्माण को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा दिया है, विदेशी निवेश आकर्षित किया और नवाचार को बढ़ावा दिया है। इससे लाखों नौकरियों का सृजन हुआ है और कौशल विकास को बढ़ावा मिला है, जिससे आर्थिक विकास में योगदान मिला है। इस पहल ने विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में, एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को भी मजबूत किया है। कुल मिलाकर, इसने भारत के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने और विश्व मंच पर इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

### 2.1 मेक इन इंडिया – उद्देश्य

मेक इन इंडिया मिशन के कई लक्ष्य हैं:

1. विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर को बढ़ाकर 12-14% प्रति वर्ष करना।
2. 2022 तक विनिर्माण क्षेत्र में 100 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां सृजित करना।

3. 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाकर 25% लक्ष्य रखा गया था।
4. समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए शहरी गरीबों और ग्रामीण प्रवासियों के बीच आवश्यक कौशल का सृजन करना।
5. विनिर्माण क्षेत्र में घरेलू मूल्य संवर्धन और तकनीकी गहराई में वृद्धि।
6. पर्यावरणीय रूप से सतत विकास।
7. भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।

## 2.2 मेक इन इंडिया: मुख्य बिंदु

केंद्र सरकार की यह योजना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में निवेश के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा के प्रवाह पर केंद्रित है। यह उचित सुविधाएँ प्रदान करके और भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण अपनाकर विदेशी निवेशकों को आकर्षित करती है। एफआई के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किए जा रहे हैं जो उनके प्रश्नों का त्वरित उत्तर प्रदान करते हैं। यह वंदे भारत, आईएनएस विक्रान्त आदि जैसी योजनाओं में अधिक से अधिक निवेशकों को आकर्षित करने में सक्षम है।



चित्र 1: मेक इन इंडिया: मुख्य बिंदु

## 3. "मेक इन इंडिया" का विकास

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर, 2014 को शुरू की गई 'मेक इन इंडिया' पहल अपनी दसवीं वर्षगांठ मना रही है। यह रणनीतिक कदम भारत के महत्वाकांक्षी राष्ट्र-निर्माण प्रयासों को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण रहा है, जिसका उद्देश्य देश को 27 क्षेत्रों में नवाचार, डिज़ाइन और विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस पहल के उद्देश्यों में स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, प्रमुख डाउनस्ट्रीम परिचालनों का विकास और उच्च तकनीक उत्पादन/उन्नत विनिर्माण में निवेश को प्रोत्साहित करना शामिल था। यह दो अलग-अलग चरणों में किया गया:

### 3.1 मेक इन इंडिया - चरण

- चरण 1 - मेक इन इंडिया 1.0 (2014-19): अध्ययन और अवसर प्रस्ताव



**चित्र 2: भारतीय सरकार सीमा पार के निर्माताओं के साथ बातचीत**

वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत 'उन्नत स्थानीय मूल्य संवर्धन एवं निर्यात के लिए संचालन समिति' (SCALE) का गठन प्रत्येक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों/बाधाओं की पहचान करने के लिए किया गया था, जिनका समाधान करने पर तत्काल सुधार हो सकता है, दीर्घकालिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं तथा भारत में विनिर्माण में तेजी आ सकती है।

#### **परिवर्तन लाने वाली नीतियां**

विनिर्माण क्षेत्र में भारत का प्राथमिक दृष्टिकोण नीतिगत सुधारों के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता का निर्माण करने पर केंद्रित है। चार प्रमुख पहलों को प्राप्त करने के लिए कई पहल की गईं:

### तालिका 1: चरण 1 के मुख्य उद्देश्य

पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं	आयात कम करें	निर्यात बढ़ाएँ	मांग को बढ़ावा
सभी औद्योगिक पैमानों पर विकास के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना।	घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात में कटौती करने के लिए उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों को रणनीतिक रूप से बढ़ावा देना।	भारत की वैश्विक विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को बढ़ाने के लिए नीतियों को लागू करना।	घरेलू मांग को प्रोत्साहित करने के लिए सोर्सिंग मानदंडों को संशोधित करें और नीतिगत बाधाओं को हटाएँ।
<b>लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रमुख पहल</b>			
पीएलआई योजना: भारत निर्मित इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री में वृद्धि पर 4-6% प्रोत्साहन।	रेफ्रिजरेटर्स युक्त एयर कंडीशनर (एसी) के आयात पर प्रतिबंध।	पीएलआई योजना: भारत निर्मित चिकित्सा उपकरणों की बिक्री में वृद्धि पर 5% प्रोत्साहन।	प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक: विकेंद्रीकरण और विनियमन के माध्यम से बंदरगाह बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना।

#### • चरण 2 - मेक इन इंडिया 2.0 (2019-24): कार्रवाई और कार्यान्वयन

यह चरण ठोस कार्रवाई और नीतियों के कार्यान्वयन पर केंद्रित है, जिसमें शामिल हैं:

- ✓ नई विनिर्माण इकाइयों के लिए कॉर्पोरेट कर को 22% से घटाकर 15% (2019-2024) करना, जिससे भारत दक्षिण-पूर्व एशियाई बाजार में प्रतिस्पर्धी बन जाएगा
- ✓ 27 क्षेत्रों को कवर करते हुए पहल का विस्तार करना, उपलब्धियों को बढ़ावा देना, और भारत की वैश्विक विनिर्माण क्षमता को सुदृढ़ करना
- ✓ इन उपायों ने, विभिन्न अन्य पहलों के साथ, भारत को वैश्विक व्यापार और वाणिज्य परिदृश्य में एक मजबूत ताकत बनने की ओर अग्रसर किया है।

"मेक इन इंडिया 2.0" ने अपने फोकस को बढ़ाकर 27 प्रमुख क्षेत्रों को शामिल कर लिया है, जबकि पहले इसमें 25 क्षेत्र शामिल थे। नए क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जीनोमिक्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

- **मौजूदा क्षेत्रों को मजबूत करना:** यह पहल कपड़ा, ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे पारंपरिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के साथ-साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी उन्नयन पर नए सिरे से जोर दे रही है।
- **नीति एवं विनियामक सुधार:** अनुपालन को सरल बनाने तथा नई विनिर्माण इकाइयों के लिए कॉर्पोरेट कर की दर को घटाकर 15% करने के लिए विनियमों को और अधिक सुव्यवस्थित किया गया है।
- **डिजिटल इंडिया एकीकरण:** "डिजिटल इंडिया" पहल के साथ एकीकरण प्राथमिकता रही है, जिससे विनिर्माण प्रक्रियाओं में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा, साइबर सुरक्षा में वृद्धि होगी और उद्योग 4.0 प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- **हरित विनिर्माण:** नवीकरणीय ऊर्जा और संसाधन-कुशल प्रौद्योगिकियों के उपयोग सहित टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल विनिर्माण प्रथाओं को बढ़ावा देना।
- **वित्तीय प्रोत्साहन:** उत्पादन-लिंकड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं जैसे कार्यक्रमों के लिए बजट में वृद्धि करना, उन्हें अधिक क्षेत्रों तक विस्तारित करना तथा बेहतर मापनीयता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए निवेश सीमा में वृद्धि करना।
- **कौशल विकास:** व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान दिया, जिसका लक्ष्य 2025 तक उन्नत विनिर्माण और प्रौद्योगिकी-उन्मुख भूमिकाओं में 10 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करना है।

### ● मेक इन इंडिया 3.0 (प्रस्तावित)

जैव प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे उच्च तकनीक क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए विशेष प्रोत्साहन के साथ अनुसंधान एवं विकास व्यय को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया जाएगा।

- **निर्यात संवर्धन:** भारत की निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए आक्रामक रणनीतियाँ लाई गयी। इसमें निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तुएँ (ईपीसीजी) योजना को बढ़ाना और विशिष्ट लाभों के साथ विशेष निर्यात क्षेत्र स्थापित करना शामिल है।
- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण:** रणनीतिक व्यापार साझेदारी बनाकर, रसद को अनुकूलित करके और व्यापार बाधाओं को कम करके वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति को मजबूत करना।
- **शहरीकरण से जुड़ा विनिर्माण:** शहरी नियोजन रणनीतियों को विनिर्माण आवश्यकताओं के अनुरूप शामिल करें। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि शहरीकरण औद्योगिक विकास से प्रेरित और उसका समर्थन करता है।
- **लचीलापन और पुनर्प्राप्ति:** वैश्विक व्यवधानों, जैसे महामारी या भू-राजनीतिक तनाव, के विरुद्ध आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को मजबूत करने के लिए तंत्र विकसित करना, जिससे कच्चे माल और संसाधनों का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित हो सके।

### 3.2 भारत की विनिर्माण यात्रा: तब और अब

भारत में विनिर्माण क्षेत्र निर्मित स्थानों पर विशेष ध्यान देते हुए तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत में विनिर्माण स्थलों को पट्टे पर देने की माँग पिछले तीन वर्षों में 4.5 गुना बढ़ी है, जो 2020 में 32 लाख वर्ग फुट से बढ़कर 2023 में 138 लाख वर्ग फुट हो गई है (2024 के लिए 16 लाख वर्ग फुट अनुमानित)। भारत के वृहद-आर्थिक आंकड़ों पर एक नज़र:

भारतीय अर्थव्यवस्था			
	तब 2014-15	अब 2023-24	2030 तक (आगे)
 सस्त्र घलकराष (GDP)	2.0 उसदीती अल	3.6 उसदीती वल	7.3 उसदीती अल
 प्रेस्य तिदीशी नियेल (FDI)	45.1 अयं लिध्यात	71.0 अयं लिध्यात	100 अयं लिध्यात
 माल निरयत (वायगु)	317.5 अयं लिध्यात	437.1 अयं लिध्यात	1 गुलीनी सज
 तिनधिवयणं रोमगुर	54.7 मोलिन	63.1 मोलिन	—
 Ease of Doing Business (EoDB)	142 2014	63 2020*	—

\* वारुमे ससुमी ससुती 2020 के साव वंज आवते 2020 राधनतन ररत भीपन का कगुरत का उस व्थस ।  
\* भारत से लुपर मे प्रतसकरम गुनी से सांघम का वारुडा कर्मधरुदि वेतार धा.)

सुत: विश्व बैंक, इन्वेस्ट इंडिया, आईबीईएफ, पीआईबी, डीजीसीआईएस

### चित्र 3: भारत की विनिर्माण यात्रा

### 3.2.1 एडवांटेज इंडिया: विनिर्माण क्षेत्र की विकास गाथा

मैनुफैक्चरिंग्स उद्योग	तब 2014-15	अब 2023-24	वृद्धि X गुना
मोडर्न फौन निर्यात	2.0 US\$ अरब	1.5 US\$ अरब	1.5x
असेंबलिंग वाहन	0 (अन्न-असुरित)	3 (अन्न-असुरित)	-
खाद्यकृषि क्षेत्र की स्थापित रखवता (GVA)	75.5 मिमाबोट	28.0 मिमाबोट	2.6x
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का सकल मूल्य वार्हित (GVA)	21.9 US\$ अरब	28.0 US\$ अरब	1.3x
समापत इस्पात का निर्यात	5.6 मिलियन टन	7.5 मिलियन टन	1.3x
औषधि ओर दवा निर्यात	15.1 US\$ अरब	27.9 US\$ अरब	1.8x
रक्षा उपतमन मूल्य	6.5	15.3	2.4x
Drug और दवा निर्यात	15.1 US\$ अरब	27.9 US\$ अरब	1.8x
रक्षा ओझाघमशक मूल्य	6.5 US\$ अरब	15.3 US\$ अरब	2.4x
औषधि ओर दवा निर्यात	6.5 US\$ अरब	15.3 US\$ अरब	2.4x
रक्षा उपदादन मूल्य	6.5 US\$ अरब	15.3 US\$ अरब	2.4x

स्रोत: विश्व बैंक, इन्वेस्ट इंडिया, आईबीईएफ, पीआईबी, डीजीसीआईएस

### चित्र 4: एडवांटेज इंडिया: विनिर्माण क्षेत्र की विकास गाथा

#### तालिका 2: क्षेत्रवार वृद्धि और प्रमुख निवेशक

क्षेत्र	विकास	निर्यात / आयात	प्रमुख निवेशक
इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (मोबाइल फोन / दूरसंचार / ड्रोन और ड्रोन घटक / आईटी हार्डवेयर / श्वेत वस्तुएं)	भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र वित्त वर्ष 23 में 155 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ गया, जो वित्त वर्ष 2016 से लगभग चार गुना	मोबाइल निर्यात 2014 की तुलना में 77 गुना बढ़ा है। वर्तमान में, 99% भारतीय मोबाइल फोन घरेलू स्तर पर	फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, सैमसंग, ऑप्टिमस, पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, लावा इंटरनेशनल, भगवती प्रोडक्ट्स

	अधिक है, जो मुख्य रूप से मोबाइल फोन द्वारा संचालित है।	बनाए जाते हैं, जो 2014-15 के 26% से काफी अधिक है।	
चिकित्सा उपकरण/फार्मास्युटिकल दवाएं/दवा मध्यस्थ और एपीआई	भारतीय दवा उद्योग पिछले 5 वर्षों में 1.3 गुना बढ़ा है (2018 में 38 अरब अमेरिकी डॉलर से 2023 में 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक)। 2030 तक इसके 130 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।	निर्यात लगभग दोगुना हो गया (2013-14 में 15.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 27.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर)।  फार्मा क्षेत्र में कच्चे माल के आयात में उल्लेखनीय कमी।	पैनेसिया मेडिकल टेक्नोलॉजीज, सीमेंस हेल्थकेयर, एलेंजर्स मेडिकल सिस्टम्स, अरबिंदो फार्मा, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स, ऑर्किड बायो-फार्मा, रेड्डीज लैबोरेटरीज, बायोकॉन, स्ट्राइड्स फार्मा साइंस, प्रीमियर मेडिकल
इलेक्ट्रिक वाहन	यह क्षेत्र, जो 2014 में अस्तित्व में नहीं था, अब 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया है।	2022 में निर्यात 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया	हुंडई, हीरो, स्कोडा, किआ, बीएमडब्ल्यू, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एथर, सिंपल एनर्जी, ओला
रक्षा एवं एयरोस्पेस	देश में रक्षा उत्पादन का मूल्य पिछले 10 वर्षों में 2.3 गुना बढ़ा (वित्त वर्ष 2024 में यह 15.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो 2014 में 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था)	निर्यात में 21 गुना वृद्धि हुई है और यह 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, तथा 85 से अधिक देशों तक पहुंच गया है।	आरव मानवरहित प्रणालियाँ, एस्तेरिया एयरोस्पेस, एक्सोल्यूट कंपोजिट्स बेंगलोर, एड्रोइटेक सूचना प्रणालियाँ

नवीकरणीय ऊर्जा	मार्च 2023 तक, संचयी पी.वी. मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता बढ़कर लगभग 38GW हो गई, जो 2020 (15GW) की क्षमता से दोगुनी है।	पिछले एक वर्ष में भारतीय पी.वी. निर्यात (मूल्य के हिसाब से) 5 गुना से अधिक बढ़ चुका है।	अडानी ग्रीन एनर्जी, सुजलॉन एनर्जी, रिन्यू पावर, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, वेस्टास, नॉर्डेक्स, गुरित
विशेष इस्पात	भारत विश्व में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है तथा चीन को पीछे छोड़कर विश्व में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बनने की ओर अग्रसर है।	2014 से तैयार इस्पात के निर्यात में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है	आर्सेलर मित्तल निप्पाॉन स्टील इंडिया, जिंदल स्टील ओडिशा, द टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया, भूषण पावर एंड स्टील
खाद्य प्रसंस्करण	खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 2014-15 में 21.91 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 27.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।	पिछले 10 वर्षों में कृषि निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात का हिस्सा 13.7% से बढ़कर 25.6% हो गया है।	ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हल्दीराम सैक्स, पारले बिस्कुट, बीकाजी फूड्स, आईटीसी, बीकानेरवाला फूड्स, अनमोल इंडस्ट्रीज

स्रोत: पीआईबी, आईबीईएफ, ऊर्जा आर्थिक एवं वित्तीय विश्लेषण संस्थान, भारतीय फार्मास्युटिकल एलायंस, डीजीसीआईएस, नीति आयोग

### तालिका 3: भारत में वैश्विक निवेश इरादे

कंपनी	मुख्यालय देश	क्षेत्र	मिलियन अमरीकी डॉलर	जगह
हुंडई मोटर्स	दक्षिण कोरिया	ऑटोमोटिव	2,756	तमिलनाडु
स्कोडा-ऑटो वोक्सवैगन	जर्मनी	ऑटोमोटिव	1,797	महाराष्ट्र
आईएमआर धातुकर्म संसाधन	स्विट्ज़रलैंड	धातु	1,438	आंध्र प्रदेश
हुंडई मोटर्स	दक्षिण कोरिया	ऑटोमोटिव	839	महाराष्ट्र
माइक्रोन	यूएसए	अर्धचालक (सेमीकंडक्टर)	825	गुजरात
टीडीके कॉर्प	जापान	इलेक्ट्रानिक्स	779	हरयाणा
निसान, रेनॉल्ट	जापान, फ्रांस	ऑटोमोटिव	635	तमिलनाडु
नेस्ले	स्विट्ज़रलैंड	खाद्य और पेय पदार्थ	599	ओडिशा
विनफास्ट	वियतनाम	ऑटोमोटिव	500	तमिलनाडु
सेंट गोबेन	फ्रांस	निर्माण	407	तमिलनाडु
एएमडी	यूएसए	अर्धचालक (सेमीकंडक्टर)	400	कर्नाटक
पौ चैन	ताइवान	जूते	276	तमिलनाडु
मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक	जापान	इलेक्ट्रानिक्स	227	तमिलनाडु
शूटाउन	चीन	जूते	204	तमिलनाडु

मॉडेलेज़	यूएसए	खाद्य और पेय पदार्थ	192	आंध्र प्रदेश
बोइंग	यूएसए	एयरोस्पेस	192	कर्नाटक
विस्ट्रॉन	ताइवान	इलेक्ट्रॉनिक्स	180	आंध्र प्रदेश
सीमेंस हेल्थिनियर्स	जर्मनी	स्वास्थ्य देखभाल	156	कर्नाटक
यंगोन कॉर्पोरेशन	दक्षिण कोरिया	कपड़ा	120	तेलंगाना
एबीबी	स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड	इंजीनियरिंग	120	महाराष्ट्र

\*कंपनी समाचार लेखों से। \*रुपये में निवेश घोषणाओं के लिए, रूपांतरण हेतु 1US\$ = 82 INR की विनिमय दर का उपयोग किया गया है।

#### तालिका 4: भारत में घरेलू निवेश की मंशा

कंपनी	क्षेत्र	मिलियन अमरीकी डॉलर	जगह
अदानी एनर्जी	ऊर्जा	100,000	गुजरात
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स + पीएसएमसी	अर्धचालक (सेमीकंडक्टर)	10,905	गुजरात
मारुति सुजुकी	ऑटोमोटिव	3,835	गुजरात
टाटा अर्धचालक (सेमीकंडक्टर) असेंबली	अर्धचालक (सेमीकंडक्टर)	3,235	असम
टाटा मोटर्स	ऑटोमोटिव	1,000	तमिलनाडु
एक्साइड बैटरी	ईवी बैटरी	719	कर्नाटक
केन्स सेमीकॉन	अर्धचालक (सेमीकंडक्टर)	599	गुजरात
टाटा केमिकल्स	रसायन	479	गुजरात
सनोफी हेल्थकेयर	फार्मा	431	तेलंगाना

एप्सिलॉन कार्बन	रासायनिक	240	ओडिशा
-----------------	----------	-----	-------

### 3.2.2 भारत किस ओर जा रहा है?

स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर अर्थात् 2047 तक भारत की आकांक्षा वास्तव में आत्मनिर्भर विकसित राष्ट्र या 'विकसित भारत' बनने की है।

#### तालिका 5: आर्थिक विकास

अर्थव्यवस्था	दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा
विनिर्माण जीडीपी	15 गुना बढ़कर 6.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचना
सेवा सकल घरेलू उत्पाद	13 गुना बढ़कर 20 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचना
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	12 गुना बढ़कर 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचना
निर्यात	12 गुना बढ़कर 8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचना

स्रोत: इन्वेस्ट इंडिया, दावोस पेपर।

पिछले दशक में, 'मेक इन इंडिया' ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि को गति दी है। जैसे-जैसे भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने, विनिर्माण जीडीपी को 15 गुना बढ़ाने और निर्यात को 12 गुना बढ़ाने के अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है, 'मेक इन इंडिया' ने इन आकांक्षाओं के लिए एक मज़बूत आधारशिला रखी है। निरंतर नीतिगत समर्थन और प्रमुख क्षेत्रों पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करने के साथ, भारत एक वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बनने के अपने लक्ष्य को साकार करने की राह पर है।

### 3.2.3 रिकॉर्ड एफडीआई से 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा मिलेगा

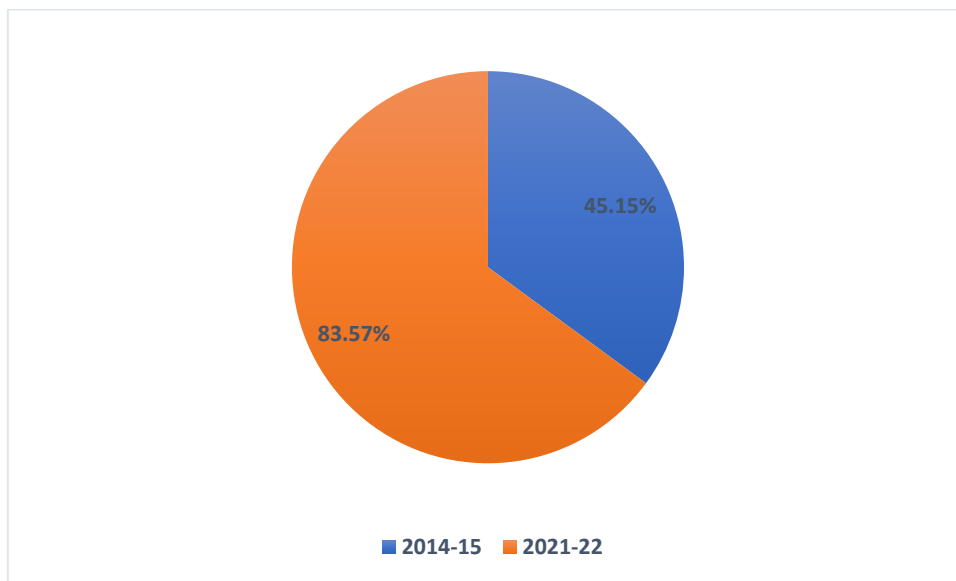
मेक इन इंडिया पहल की सफलता को रिकॉर्ड तोड़ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह से काफी बल मिला है, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों के सरलीकरण और व्यापार करने में आसानी में सुधार से प्रेरित है। भारत अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) सूचकांक में शीर्ष 100 देशों में शुमार है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह लगातार बढ़ रहा है, जो 2014-15 में 45.14 बिलियन डॉलर से शुरू होकर 2021-22 में रिकॉर्ड 84.83 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। अप्रैल 2014 और मार्च 2024 के बीच, भारत ने 667.41 बिलियन

डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया, जो पिछले 24 वर्षों में प्राप्त कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लगभग 67% है। वित्त वर्ष 2023-24 में, कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह 70.95 बिलियन डॉलर रहा, जिसमें इक्विटी प्रवाह 44.42 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया,



**चित्र 5: भारत में एफडीआई (FDI) का रिकॉर्ड तोड़ निवेश**

भारत सरकार संभावित निवेशकों की पहचान करने के लिए मेक इन इंडिया कार्ययोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निवेश सुविधा के अंतर्गत निरंतर प्रयास कर रही है। मेक इन इंडिया के तहत देश में निवेश आकर्षित करने के लिए कार्यक्रमों, शिखर सम्मेलनों, रोड शो और अन्य प्रचार गतिविधियों के आयोजन हेतु विदेश स्थित भारतीय मिशनो और राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जा रही है।



**चित्र 6: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)**

भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर का अब तक का सर्वाधिक वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह दर्ज किया है, जबकि 2014-15 में यह 45.15 अरब अमेरिकी डॉलर था। वित्त वर्ष 2014-2020 में भारत को 358.30 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह प्राप्त हुआ था, जो पिछले 20 वर्षों में दर्ज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (681.87 अरब अमेरिकी डॉलर) का 53 प्रतिशत है। भारत विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए तेजी से एक पसंदीदा देश के रूप में उभर रहा है। विनिर्माण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह वित्त वर्ष 2021-22 में 76% बढ़ा है (21.34 अरब अमेरिकी डॉलर), जबकि पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में यह 12.09 अरब अमेरिकी डॉलर था।

#### 4. मध्य प्रदेश में मेक इन इंडिया के अंतर्गत प्रमुख विकास

##### ✓ आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास

मध्य प्रदेश में औद्योगिक गलियारों के विकास ने सतत औद्योगिक विकास के लिए एक मज़बूत आधार प्रदान किया है। दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) राज्य के पश्चिमी जिलों, जिनमें रतलाम, महू और पीथमपुर शामिल हैं, से होकर गुजरता है। यह रणनीतिक संरक्षण मध्य प्रदेश को भारत के सबसे बड़े विनिर्माण और व्यापार केंद्र के साथ एकीकृत करता है, जिससे बंदरगाहों, प्रमुख बाज़ारों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित होती है। इसी प्रकार, भोपाल-इंदौर औद्योगिक गलियारा राज्य के दो प्रमुख शहरी केंद्रों को जोड़ने के लिए विकसित किया जा रहा है, जिससे एक एकीकृत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा। ये गलियारे न केवल रसद दक्षता में सुधार करते हैं, बल्कि विनिर्माण, भंडारण और संबंधित बुनियादी ढाँचे में बड़े पैमाने पर निवेश को भी प्रोत्साहित करते हैं।

मध्य प्रदेश ने पिछले 10 वर्षों में एक मज़बूत आर्थिक स्थिति बनाए रखी है। वित्त वर्ष 2025 में इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) वर्तमान मूल्यों पर 15.22 ट्रिलियन रुपये (177.70 बिलियन अमेरिकी डॉलर) रहा और कृषि, विनिर्माण, सेवाओं और बुनियादी ढाँचे के विकास से इसकी वृद्धि स्थिर रही है। वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2025 तक GSDP में 12.00% की वृद्धि का अनुमान है, जो औद्योगिक और निवेश प्रवाह में अच्छी वृद्धि दर्शाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में भी राज्य ने अपनी स्थिति मज़बूत बनाए रखी है और लगातार वृद्धि दर्ज करते हुए बड़े निजी और सरकारी निवेश आकर्षित किए हैं।

बढ़ती समृद्धि का संकेत प्रति व्यक्ति जीएसडीपी से भी मिलता है, जो वित्त वर्ष 2024 में 1,56,381 रुपये (1,875.07 अमेरिकी डॉलर) तक पहुँच गई, जिसमें वित्त वर्ष 2016 और वित्त वर्ष 2024 के बीच 10.91 की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) रही। ये आँकड़े स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में धीमी लेकिन स्थिर वृद्धि का संकेत देते हैं, साथ ही प्रमुख क्षेत्रों में बढ़ती उत्पादकता और दक्षता को भी दर्शाते हैं। राज्य के वित्त वर्ष 2025 के बजट में बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और ऊर्जा के लिए बजटीय आवंटन, एक सतत विकास वातावरण विकसित करने की सरकार की इच्छा को दर्शाता है। सड़क, बिजली और औद्योगिक बुनियादी ढाँचे में निवेश, घरेलू और वैश्विक बाजार में राज्य की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के अलावा, तेजी से औद्योगीकरण को भी सक्षम बना रहे हैं।

### तालिका 6: मध्य प्रदेश की जीएसडीपी वृद्धि

सूचक	कीमत	अवधि
वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी	15.22 ट्रिलियन रुपये (177.70 बिलियन अमेरिकी डॉलर)	वित्त वर्ष 25
जीएसडीपी सीएजीआर	12.00%	वित्त वर्ष 16-वित्त वर्ष 25
प्रति व्यक्ति जीएसडीपी	रु. 1,56,381 (यूएस\$ 1,875.07)	वित्त वर्ष 24

#### ✓ क्षेत्रीय विकास

मेक इन इंडिया पहल के तहत मध्य प्रदेश ने उल्लेखनीय क्षेत्र-विशिष्ट विकास देखा है। ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग क्षेत्र में, पीथमपुर एक अग्रणी विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। यह क्षेत्र वोल्वो आयशर और फोर्स मोटर्स जैसी प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों का गढ़ है, जो रोजगार, सहायक उद्योगों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा दे रहा है। वस्त्र और परिधान क्षेत्र में, इंदौर और भोपाल जैसे शहरों ने वस्त्र प्रसंस्करण, रंगाई और परिधान उत्पादन के लिए मजबूत बुनियादी ढाँचा विकसित किया है, जिससे राज्य घरेलू और निर्यात बाजारों में अपनी पैठ बना रहा है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र फल-फूल रहा है, जिसे मालवा और निमाड़ जैसे उपजाऊ कृषि क्षेत्रों का समर्थन प्राप्त है, जो कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं और पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज और मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों में निवेश आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश ने नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में खुद को अग्रणी के रूप में स्थापित किया है, जहाँ रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट (750 मेगावाट) जैसी परियोजनाएँ बड़े पैमाने पर स्वच्छ ऊर्जा पहलों के लिए एक मानक के रूप में काम कर रही हैं और वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रही हैं।

#### ✓ नीतिगत समर्थन

सरकारी नीतियों ने औद्योगिक विकास को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास नीतियाँ 2014 और 2022 विविध क्षेत्रों में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पूंजीगत सब्सिडी, कर लाभ और ब्याज सब्सिडी सहित व्यापक प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। ये नीतियाँ एकल-खिड़की मंजूरी प्रणालियों के माध्यम से परियोजनाओं की त्वरित स्वीकृति पर जोर देती हैं, जिससे नौकरशाही संबंधी देरी कम से कम हो। इसके अलावा, मध्य प्रदेश पूरी तरह से डिजिटल भूमि आवंटन, पारदर्शी अनुमोदन तंत्र और सरलीकृत अनुपालन प्रक्रियाओं जैसे सुधारों के कारण व्यवसाय करने में आसानी (ईओडीबी) में लगातार उच्च स्थान पर है। यह निवेशक-अनुकूल वातावरण यह सुनिश्चित करता है कि उद्योग कम नियामक बाधाओं के साथ कुशलतापूर्वक स्थापित और संचालित हो सकें।

### ✓ कनेक्टिविटी

औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने सड़क नेटवर्क, रेल नेटवर्क, हवाई अड्डों और रसद सुविधाओं में अच्छा निवेश किया है। मनमाड-इंदौर रेलवे लाइन जैसी परियोजनाओं से इसे और बल मिलने की संभावना है, जिससे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच संपर्क बढ़ेगा और रीवा हवाई अड्डे की मंजूरी से इस क्षेत्र में व्यापार और आवाजाही में मदद मिलेगी। ये परियोजनाएँ माल के आवागमन के समय को बचाती हैं, पर्यटन को बढ़ावा देती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों को बड़े आर्थिक उपक्रमों से जोड़ती हैं।

### ✓ औद्योगिक क्लस्टर और एसईजेड

मध्य प्रदेश में विविध प्रकार के औद्योगिक क्लस्टर और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) मौजूद हैं, जो मेक इन इंडिया रणनीति का मूल आधार हैं। यहाँ पाँच कार्यरत SEZ, आठ अधिसूचित SEZ और बारह औपचारिक रूप से स्वीकृत SEZ हैं जो फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, टेक्सटाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में हैं। ये क्लस्टर केंद्रित औद्योगिक गतिविधियों को सुगम बनाते हैं, उत्पादन लागत कम करते हैं और उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। इंदौर के आसपास स्थित पीथमपुर ऑटो क्लस्टर इसका एक बेहतर उदाहरण है क्योंकि इसे मध्य भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल केंद्रों में से एक माना जा सकता है। इस क्लस्टर में 1,00,000 से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं और ये सभी प्रकार के ऑटो पार्ट्स और पूर्ण वाहन बनाने वाली 150 से ज़्यादा कंपनियाँ हैं। इन कंपनियों का बाज़ार में 97,500 करोड़ रुपये (12.75 अरब अमेरिकी डॉलर) से ज़्यादा का निवेश है, जो राज्य के निर्यात पोर्टफोलियो में योगदान देता है। इसी तरह, बैरसिया, बागरोद और उज्जैन के औद्योगिक पार्क इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उद्योगों में निवेशकों को आकर्षित करने में सक्षम होंगे। इस तरह की पहल न केवल रोज़गार सृजन में योगदान देती हैं, बल्कि राज्य में तकनीकी उपयोग, कौशल विकास और मूल्य संवर्धन को भी बढ़ावा देती हैं।

### ✓ सरकारी पहल और नीति समर्थन

मध्य प्रदेश सरकार उद्योगों और निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में अत्यंत सक्रिय रही है। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एमपीएसआईडीसी) समन्वय, उत्प्रेरक और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ समय पर पूरी हों और संसाधनों का समुचित उपयोग हो। राज्य ने कई निवेशक-अनुकूल नीतियाँ शुरू की हैं, जैसे उद्योग-विशिष्ट निवेशों पर प्रोत्साहन, वन-स्टॉप क्लियरेंस कार्यक्रम और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर सब्सिडी। इन प्रयासों का उद्देश्य न केवल घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना है, बल्कि उद्योगों का सतत विकास भी सुनिश्चित करना है।

### तालिका 7: वित्त वर्ष 25 के लिए प्रमुख बजट आवंटन

क्षेत्र	आवंटन
सड़कें और पुल	9,043 करोड़ रुपये (1.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर)
ऊर्जा क्षेत्र	13,561 करोड़ रुपये (1.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर)
स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना	12,835 करोड़ रुपये (1.50 बिलियन अमेरिकी डॉलर)
अस्पताल और औषधालय	8,335 करोड़ रुपये (973 मिलियन अमेरिकी डॉलर)
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	4,500 करोड़ रुपये (525 मिलियन अमेरिकी डॉलर)
प्राथमिक शिक्षा	23,040 करोड़ रुपये (2.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर)

इस तरह के आवंटन सरकार के उन क्षेत्रों पर जोर को दर्शाते हैं जो औद्योगिक और आर्थिक विकास को सीधे बढ़ावा देते हैं। एक्सप्रेसवे, सड़क नेटवर्क और पुल उद्योगों और व्यापार के बीच संपर्क को बढ़ाते हैं, और ऊर्जा में निवेश के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बाधित नहीं होती। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के माध्यम से मानव पूंजी का विकास होता है, जो कुशल कार्यबल के साथ मानव संसाधन के रखरखाव में महत्वपूर्ण है। ये सभी उपाय मध्य प्रदेश को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में मज़बूत बनाते हैं और मेक इन इंडिया के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

## 5. निष्कर्ष

मध्य प्रदेश मेक इन इंडिया पहल के लिए एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में विकसित हो रहा है। प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, भौगोलिक लाभ, परिवहन अवसंरचना, बढ़ती प्रशासनिक पहल और सक्रिय निवेशक मित्रता जैसे संयुक्त कारकों ने राज्य को घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों के लिए एक अनुकूल राज्य बना दिया है। औद्योगिक समूहों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) और ऑटो हब, पीथमपुर के निरंतर विकास राज्य को अतिरिक्त औद्योगिक गति प्रदान कर रहा है। इससे रोजगार के अवसर तो बढ़े ही हैं साथ ही आयात प्रतिस्थापन को भी प्रोत्साहन मिला है।

विश्लेषण से प्राप्त सांख्यिकीय निष्कर्ष दर्शाते हैं कि मेक इन इंडिया की शुरुआत के बाद से मध्य प्रदेश के आर्थिक प्रदर्शन में नाटकीय रूप से सुधार हुआ है। राज्य का विकास पथ बेहतर हुआ है, औसत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में वृद्धि हुई है, और इसके उत्पादन में उतार-चढ़ाव कम हुआ है। यह दर्शाता है कि इस कार्यक्रम का आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण और स्थिरकारी प्रभाव पड़ा है। हालाँकि, विदेशी निवेश प्रवाह दर्शाता है कि नियामक अनिश्चितता, बुनियादी ढाँचे की समस्याओं और शासन संबंधी समस्याओं के कारण निवेशकों के विश्वास में उतार-चढ़ाव आया है। दूसरे शब्दों में, हालाँकि राज्य को विकास को बढ़ावा देने वाले नीतिगत सुधारों से लाभ हुआ है, फिर भी निरंतर आर्थिक सफलता के लिए एक वैध, सुविचारित और निवेशक-समर्थक ढाँचे की आवश्यकता है।

विश्लेषण से प्राप्त सांख्यिकीय निष्कर्ष दर्शाते हैं कि मेक इन इंडिया की शुरुआत के बाद से मध्य प्रदेश के आर्थिक प्रदर्शन में नाटकीय रूप से सुधार हुआ है। राज्य का विकास पथ बेहतर हुआ है, औसत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में वृद्धि हुई है, और इसके उत्पादन में उतार-चढ़ाव कम हुआ है। यह

दर्शाता है कि इस कार्यक्रम का आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण और स्थिरकारी प्रभाव पड़ा है। हालाँकि, विदेशी निवेश प्रवाह दर्शाता है कि नियामक अनिश्चितता, बुनियादी ढाँचे की समस्याओं और शासन संबंधी समस्याओं के कारण निवेशकों के विश्वास में उतार-चढ़ाव आया है। दूसरे शब्दों में, हालाँकि राज्य को विकास को बढ़ावा देने वाले नीतिगत सुधारों से लाभ हुआ है, फिर भी निरंतर आर्थिक सफलता के लिए एक वैध, सुविचारित और निवेशक-समर्थक ढाँचे की आवश्यकता है।

विश्लेषण के निष्कर्ष में, पेपर से पता चलता है कि मेक इन इंडिया परियोजना का निर्माण भारत के विनिर्माण पहलू को बदलने के केंद्र में रहा है और मध्य प्रदेश इस राष्ट्रीय पहलू के सबसे महत्वपूर्ण लाभार्थियों में से एक रहा है। मेक इन इंडिया 1.0 से 2.0 में क्रमिक वृद्धि के साथ-साथ रणनीतिक नीति में बदलाव, ढांचागत विकास और क्षेत्र में प्रोत्साहन ने राज्य को अपनी औद्योगिक पृष्ठभूमि को मजबूत करने और ऑटोमोबाइल, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, नवीकरणीय ऊर्जा और खाद्य प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर निवेश करने में मदद की है। जीएसडीपी में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय के साथ-साथ औद्योगिक गलियारों और एसईजेड में वृद्धि का मतलब है कि राज्य में संरचनात्मक परिवर्तन व्यवस्थित है। फिर भी, एफडीआई प्रवाह और वर्तमान विनियामक और ढांचागत सीमाओं में लगातार बदलाव से संकेत मिलता है कि स्थिति में लगातार सुधार को नीतियों में निरंतर सुधार और अधिक प्रभावी शासन योजनाओं को लागू करके हासिल करना होगा। संक्षेप में, परिणाम इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की स्थापना ने मध्य प्रदेश की औद्योगिक क्षमता को काफी सशक्त बनाया है, रोजगार बढ़ाया है, और लंबे समय में नवाचार के आधार पर आर्थिक विकास का एक स्थायी ढांचा प्रदान किया है।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- 1) पांडे एस. और अग्रहरि वी. (2023) - मेक इन इंडिया: विकास पहल पर एक संक्षिप्त अध्ययन, इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, खंड 5, अंक 6, पृष्ठ 1-6
- 2) डॉ. स्वाति पांडे और डॉ. विपिन अग्रहरि (2023). मेक इन इंडिया: विकास पहल पर एक संक्षिप्त अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च (IJFMR) E-ISSN: 2582-2160, खंड 5, अंक 6
- 3) आत्मा राम (2022). भारत में सतत आर्थिक विकास के लिए मेक इन इंडिया। IJCSPUB | खंड 12, अंक 4, अक्टूबर 2022 | ISSN: 2250-1770
- 4) यादव, प्रियंका (2018), "मेक इन इंडिया: विकास के लिए एक पहल", आईएमई जर्नल 12(1-2), 22-27
- 5) मिश्रा, प्रतीक्षा, तरुणा (2016). विनिर्माण क्षेत्र में विकास के चालक के रूप में मेक इन इंडिया की भूमिका। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च, 2(1), 591-594।
- 6) अनेजा, पुनीत, (2016). मेक इन इंडिया: भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए नया प्रतिमान. इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च, 5(4) 2250 - 1991
- 7) साहू डी., मथियाझगन एम.के. भारत में आर्थिक विकास: क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह मायने रखता है?, द सिंगापुर इकोनॉमिक रिव्यू 2003; 48: 151-171।
- 8) बिश्रोई वी. (2017). मेक इन इंडिया पहल: सतत विकास की कुंजी। साउथ एशियन जर्नल ऑफ मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट रिसर्च, 9(3), 78-85. <https://doi.org/10.5958/2249-877X.2019.00013.4>
- 9) सक्सेना पी., यादव एस., श्रीवास्तव आर., और अग्रवाल ए. (2017). मेक इन इंडिया दो साल और उसके बाद - एक आलोचनात्मक मूल्यांकन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, आईटी एंड इंजीनियरिंग, 7(6), 87-96. <http://www.ijmra.us>
- 10) राज्यसभा टीवी (2014). 'मेक इन इंडिया' पहल के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण। [https://www.youtube.com/watch?v=GrUqB0\\_IWmUK](https://www.youtube.com/watch?v=GrUqB0_IWmUK) Mantra (2016) से लिया गया। एमआईआई पुरस्कार - 2015: 'भारत को विनिर्माण केंद्र कैसे बनाया जाए' विषय पर समूह चर्चा।



## Author's Declaration

I as an author of the above research paper/article, here by, declare that the content of this paper is prepared by me and if any person having copyright issue or patent or anything otherwise related to the content, I shall always be legally responsible for any issue. For the reason of invisibility of my research paper on the website /amendments /updates, I have resubmitted my paper for publication on the same date. If any data or information given by me is not correct, I shall always be legally responsible. With my whole responsibility legally and formally have intimated the publisher (Publisher) that my paper has been checked by my guide (if any) or expert to make it sure that paper is technically right and there is no unaccepted plagiarism and hentriacontane is genuinely mine. If any issue arises related to Plagiarism/ Guide Name/ Educational Qualification /Designation /Address of my university/ college/institution/ Structure or Formatting/ Resubmission /Submission /Copyright /Patent /Submission for any higher degree or Job/Primary Data/Secondary Data Issues. I will be solely/entirely responsible for any legal issues. I have been informed that the most of the data from the website is invisible or shuffled or vanished from the database due to some technical fault or hacking and therefore the process of resubmission is there for the scholars/students who finds trouble in getting their paper on the website. At the time of resubmission of my paper I take all the legal and formal responsibilities, If I hide or do not submit the copy of my original documents (Andhra/Driving License/Any Identity Proof and Photo) in spite of demand from the publisher then my paper maybe rejected or removed from the website anytime and may not be consider for verification. I accept the fact that as the content of this paper and the resubmission legal responsibilities and reasons are only mine then the Publisher (Airo International Journal/Airo National Research Journal) is never responsible. I also declare that if publisher finds Any complication or error or anything hidden or implemented otherwise, my paper maybe removed from the website or the watermark of remark/actuality maybe mentioned on my paper. Even if anything is found illegal publisher may also take legal action against me.

**Janardan Kukreja**  
**Prof. Ajay Kumar Mandil**  
**Prof. Sanjeev Gupta**

\*\*\*\*\*